



तरुण छत्तीसगढ़

■ रायपुर, गुरुवार 3 अगस्त 2023 ■ श्रावण कृष्ण पक्ष-2 ■ वर्ष- 39 ■ अंक-126 ■ पृष्ठ-8 ■ डाक संस्करण 4 अगस्त 2023 ₹ 1.00

E-mail:
tarunpressraipur@gmail.com
tarun_press@yahoo.co.in

Web:
www.tarunchhattisgarh.in
facebook.TarunChhattisgarh
Twitter - Tchhattisgarh36
Instagram - tarunchhattisgarh.raipur

phone: 0771-2543112

संक्षेप

बघेल ने दी राज्यपाल को
जननिधि पर बधाई

रायपुर, 3 अगस्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रेस के राज्यपाल बिस्था भूषण हरिचंदन को बधाई पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा गजपाल हरि चंदन के दीयायु और स्वयं जीवन की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।

**आधी रात गांव में
मटी अफरा तफरी**

जरापुर, 3 अगस्त बीती रात एक गांव में चर्चा कृत अफरा तफरी मच गई जब एक दर्तल हाथी अचानक एक बस्ती में घुस गया और मकान तोड़े लगा। रात को हाथी की दस्तक देख बस्ती के लोग जान बचाकर भगाने लगे। इसी भागने के क्रम में एक महिला को दर्तल ने कुचल दिया और महिला की मौत हो गयी। घटना जिले के कांसावल बन पंक्षिकृत की है। बीती रात बहाने के देखरी गांव में एक दर्तल ने न केवल जमकर उत्पात मचाया बल्कि एक 50 वर्षीय महिला की जान भी ले ली। बताया जा रहा है कि आधी रात को दर्तल हाथी बस्ती में घुस गया और घर में तोड़े कोड़े करने लगा। हाथी देख लोग घर ढौड़कर भगाने लगे। लोगों को भगते देख हाथी ने भी ग्रामीणों को दौड़ाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में सुमित बैंझ नाम की एक महिला दर्तल के चपेट में आ गयी। घटना की सूचना पर धूलिस मौके पर पुलिस ने जानकारी देते हुए उनकी हत्या कर दिया। मृतकों

मानसिक रोगी ने की पत्नी व 3 बेटियों की हत्या

■ तरुण छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, 3 अगस्त

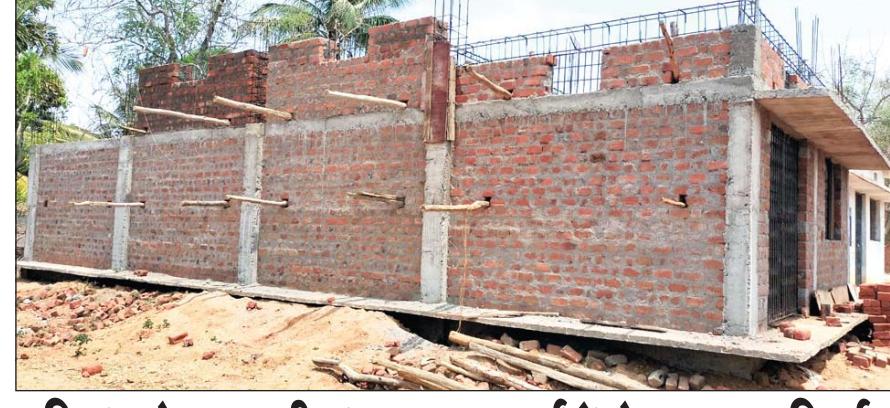
छत्तीसगढ़ की जांजगीर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी सहित 3 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना प्रिलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस मार्ग कायम कर जांच में जुट गई है और आरोपी वाहन सहित 3 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना प्रिलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस मार्ग कायम कर जांच में जुट गई है। वहीं आरोपी को हिंसात में ले लिया

का नाम पत्नी मोंगरा 40 वर्ष, पूजा 16, भाय लक्ष्मी 10, याचना 6 वर्ष है। हत्या के बारात



पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं आरोपी को हिंसात में ले लिया एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को कल रात सरपंच से सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव के एक घर में महिला समेत तीन बच्चों का शब पड़ा हांसा है। प्रथम दृश्य देखने से लगता है कि उनके साथ कोई घटना हुई है। घटना की सूचना पर चौकी प्रभारी अपने बल के साथ पहुंचे। बाद में एसपीओं और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। इस मामले में पता चला कि मृतकों का पति पिछले आठ 10 साल से मानसिक रूप से अस्वस्था रहा है और घटना के बाद से वह फरार है। जिसके बाद इस मामले में तुरंत मर्ग कायम कर आज सुबह पंचनामा की कार्रवाई की गई है। साथ ही पोस्टमर्मट के लिए शवों को रखाना कर दिया गया है। इस मामले में लिया गया है। फिलहाल, इस तीन बच्चों पर धोगा से हमता के साथ-साथ घटना पर पहुंचने पर धोगा देने के बाद आरोपी घर का दरवाजा बंद कर फरार हो गया। इस हत्याकांड को आरोपी देशराज करण्य की मानसिक स्थित टीका दिया था। इस घटना की जानकारी नहीं है, विगत 10 साल से उसके देवरी गांव में जुट गई। घटना की रात तीन बच्चों के बाद से वह तीन बच्चों पर धोगा से हमता के साथ-साथ घटना पर पहुंचने पर धोगा देने के बाद आरोपी घर की जांच कर रही है। घटना की जानकारी देते हुए

एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को कल रात सरपंच से सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव के एक घर में महिला समेत तीन बच्चों का शब पड़ा हांसा है। प्रथम दृश्य देखने से लगता है कि उनके साथ कोई घटना हुई है। घटना की सूचना पर चौकी प्रभारी अपने बल के साथ पहुंचे। बाद में एसपीओं और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। इस मामले में पता चला कि मृतकों का पति पिछले आठ 10 साल से मानसिक रूप से अस्वस्था रहा है और घटना के बाद से वह फरार है। जिसके बाद इस मामले में तुरंत मर्ग कायम कर आज सुबह पंचनामा की कार्रवाई की गई है। साथ ही पोस्टमर्मट के लिए शवों को रखाना कर दिया गया है। इस मामले में लिया गया है। अब जानवापी परिसर के एसपीओं सर्वे पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार किया गया है। आज या फिर कल से यह सर्वे शुरू हो सकता है। जिससे हिंदू पक्ष को एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और यह फैसले पर हिंदू पक्ष के लिए राहत की खबर सर्वे के लिए होने वाला खबर है। इस फैसले से पहले अंजुमन



प्रतिबंध के बाद भी पंचायत लाल ईंटों से करा रहा निर्माण

कांकड़, 3 अगस्त (हेमंत बेश्रो)

मोहना-मानपुर, 3 अगस्त जिले में स्कूली बच्चों से भी प्रियक अप वाहन अचानक अनियन्त्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कुल 17 बच्चे घायल हुए हैं। जिसमें कुछ बच्चों को चांकड़ आई है तो कछु गंभीर हैं। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जरी रहा। यह घायला खड़ागांव थाने क्षेत्र का है। बताया जा रहा ही कि सभी स्कूली छात्र छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में भाग लेकर अपने घर वापस लौट रहे थे तभी यह घायला हुआ। इस हादसे से शिक्षा विभाग पर सवाल उठाया है कि आखिर बच्चों को लापरवाही पूर्वक पिकअप वाहन से बचाने के बाबत क्या कर रहा था। जानकारी के अनुसार, प्रदेशभर में छत्तीसगढ़ी ओलंपिक चल रहा है। जिसमें स्कूली बच्चे अलग-अलग खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं मोहना-मानपुर जिले के बाग फुलकोड़े में भी भी खेल अन्यजित किया गया था। जिसमें शूलीय बच्चों को लापरवाही पूर्वक पिकअप वाहन से बचाने के बाबत क्या कर रहा है। इस अंदेश के बाद बच्चों के बांकड़ अपराध के लिए निर्माण कर रहा है।

कथा कहते हैं अधिकारी

तहसील नरहपुर अंतर्गत जिला जिन गांवों में सरकारी भवनों में लाल ईंटों का उपयोग किया जा रहा है वहाँ जिला पंचायत के टीम द्वारा जांच कराया जाएगा। जिच में जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार अकार्यवाही की जाएगी। साथ ही खनिज विभाग और एसपीओं को निर्देशित किया जाएगा कि इस संबंध में जांच करके उचित कार्रवाई करें। सुभित अग्रवाल, लिला पंचायत सीईओ, कांकड़

निर्माण की इकाई शुरू कि है लेकिन आज भी क्षेत्र में लाल ईंटों का उपयोग पहले की तरह ही हो रहा है। इन भवनों का निर्माण कायम ग्राम पंचायतों के द्वारा कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जब तक निर्माण के सहायकों से जानकारी ली गई है तब तक वहाँ जुट गयी है। घटना के बाद लोगों ने बचतों से बचते नजर आयी। अब देखना यह होगा कि सम्बंधितों पर कथा करारवाई की जाती है।

सुभित अग्रवाल, लिला पंचायत सीईओ, कांकड़

निर्माण की इकाई शुरू कि है लेकिन आज भी क्षेत्र में लाल ईंटों का उपयोग पहले की तरह ही हो रहा है। इन भवनों का निर्माण कायम ग्राम पंचायतों के द्वारा कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जब तक निर्माण के सहायकों से जानकारी ली गई है तब तक वहाँ जुट गयी है। घटना के बाद लोगों ने बचतों से बचते नजर आयी। अब देखना यह होगा कि सम्बंधितों पर कथा करारवाई की जाती है।

जानकारी के मुताबिक मेन गेट से सटे बच्चों की जांच कर रही है। जिसमें फाल्ट आने के बाद लोगों ने बचतों से बचते नजर आयी। अब देखना यह होगा कि सम्बंधितों पर कथा करारवाई की जाती है।

करेंट लगने से दादा-पोते की मौत

महाराष्ट्र, 3 अगस्त ■ तरुण छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के महाराष्ट्र में करेंट लगने से दादा और पोते की मौत हो गयी। घटना कोमाखान थाना इलाके के खुम्हापीरी के एक फार्म में हास्त का बताया जा रहा है। जहाँ मुख्य गेट में करेंट फैला था, जिसके चपेट में आने से दादा और पोते का मौत हो गया। वहीं स्तरुना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गयी है। जानकारी के मुताबिक गिरवाया था। जिसमें फाल्ट आने के चलते मेन गेट से करेंट आया था। जिसमें फाल्ट आने के बाद लोगों ने बचतों से बचते नजर आयी। अब देखना यह होगा कि प्रत्येक लोगों की जांच करारवाई की जाती है।

जानकारी के मुताबिक मेन गेट से करेंट आया था। जिसमें फाल्ट आने के बाद लोगों ने बचतों से बचते नजर आयी। अब देखना यह होगा कि प्रत्येक लोगों की जांच करारवाई की जाती है।

जानकारी के मुताबिक मेन गेट से करेंट आया था। जिसमें फाल्ट आने के बाद लोगों ने बचतों से बचते नजर आयी। अब देखना यह होगा कि प्रत्येक लोगों की जांच करारवाई की जाती है।

जानकारी के मुताबिक मेन गेट से करेंट आया था। जिसमें फाल्ट आने के बाद लोगों ने बचतों से बचते नजर आयी। अब देखना यह होगा कि प्रत्येक

छूत की बीमारी की तरह फैलती है हिंसा

हिंसा

डॉ सत्यवान सौरभ



बुद्धिमान लड़ाई से पहले जीतते हैं, जबकि अज्ञानी जीतने के लिए लड़ते हैं। संघर्ष के प्रति बुद्धिमान दृष्टिकोण लड़ाई या हिंसा में शामिल होने से पहले योजना बनाना और रणनीति बनाना शामिल है, जबकि अज्ञानी दृष्टिकोण परिणामों या संभावित परिणामों पर विचार किए बिना केवल लड़ना या हिंसा करना है। अर्थात् बौद्धिक विचार यह है कि किसी स्थिति का सावधानीपूर्वक आंकलन करके और सूचित निर्णय लेकर, कोई भी व्यक्ति शारीरिक युद्ध या हिंसा का सहारा लिए बिना जीत हासिल कर सकता है। यह उद्धरण सलाह देता है कि बुद्धिमानी ऐसी स्थिति को पहले से ही भांप लेने में है जो हिंसा में बदल सकती है और फिर इससे बचने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। क्या होता है जब हिंसा को टाला नहीं जा सकता? जब कूटनीति के प्रयास विफल हो जाते हैं, तब भी दुश्मन की ताकत और कमजोरियों का आंकलन करके दूसरे पक्ष पर तुरंत काबू पाने के लिए हिंसा को टाला जा सकता है। दुश्मन या विपक्षी को भ्रमित करने और उनके संसाधनों को बर्बाद करने के लिए धोखे और झूठ का भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंसा को कानून-व्यवस्था के मसले जैसा समझने के बजाय, इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौती के तौर पर लिया जाये। हिंसक बर्ताव एक महामारी है, जो छुआछूत की बीमारियों की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। जो लोग हिंसा के पीड़ित होते हैं, उनके हिंसा करने की आशका बढ़ जाती है। हिंसा को ठीक उसी तरह रोका जा सकता है, जैसे गर्भधारण से जुड़ी चुनौतियां, काम के दौरान लगने वाली चोटी या संक्रामक बीमारियों

हसा के शकार लागा का समझाना जरूरा है। बदला लन की मानसिकता नुक़सान करवाती है, ताकि वो फिर उसी हिंसक दुष्प्रभाव में न फंस जाएं। कोई शराबी है या इंग का आदी है, तो उसकी इलाज करने में मदद की जाती है। फिर उसे रोज़गार दिलाने की कोशिश होती है। तभी कोई भी शरवूस एकदम से बदला हुआ नज़र आ सकता है। लोगों के बर्ताव में बदलाव लाकर हम कई चुनौतियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। जैसे साफ़-सफ़ाई की आदत से डायरिया जैसी बीमारी को रोका जा सकता है। ये कदम तब और असरदार हो जाते हैं, जब एक पीड़ित, दूसरे की मदद करता है। वो अपने खुद के तजुर्बे साझा कर के लोगों की भरोसा जीत सकते हैं। जैसे कोई टीबी-हैंजा के मरीज़ रहे लोग इसके शकार लोगों के बीच काम करें। हिंसक बर्ताव एक महामारी है, जो युआधूत की बीमारियों की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है।

रो रोका जाता है। दिक्कत ये है कि दुनिया में हिंसा से सख्ती से निपटने की सोच हावी नहीं। इसलिए हिंसक घटनाओं पर हंगामा होते ही, तो हों या जनता, सख्त कानून की मांग करने गते हैं। इंसान अक्सर जोखिम भरा बर्ताव बरता है, खतरों से खेलता है। जैसे कि क्षासान पता होने के बावजूद स्मोकिंग करना। फिर पेट भरने के बावजूद ज्यादा खाना। जना एहतियात बरते सेक्स करना। डॉक्टर मेशा कहते हैं कि इलाज से बचाव बेहतर है। नी किसी मर्ज़ को होने से ही रोका जाए। किन, जब बात हिंसक बर्ताव की आती है, इससे निपटने का एक ही तरीका लोग बताते कानून सख्त बना दो। जैसे हाल ही में 12 लल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार पर बत की सज़ा का प्रावधान। या फिर भीड़ की सासा से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने पर हमारे देश में विचार चल रहा है। हिंसा को जन्मजात बर्ताव मान लिया गया है, जैसे बदला नहीं जा सकता। सोच यही है कि लोग हिंसा करते हैं, उन्हें सही गस्ते पर नहीं लाया जा सकता। इसलिए सख्त कानूनों की

हो की जाती है। लिकिन, सख्त कानूनों से बनती होती, तो कब की बन जाती है? दूसरी अरब और ईरान में कई जुर्मों के लिए बनना की सज़ा है।
मगर अपराध तब भी नहीं रुकते। भारत भी कई अपराधों के लिए मौत की सज़ा बनती है। मगर वो जुर्म अब भी होते हैं। हिंसा किस प्रकार बचा जा सकता है? आज देश जातीय दंगों के संदर्भ में, यह उद्घरण दें। दंगों के बीच संघर्षों को सुलझाने में नीति और बातचीत के महत्व पर प्रकाश नहीं आता है। हिंसा का सहारा लेने के बजाय, इसके सभी संबंधित पक्षों के लिए विनाशकारी नाम हो सकते हैं, बुद्धिमान नेता बातचीत कर समझौते के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान ने का प्रयास करता है। प्रायः पड़ोसी राज्यों या अर्थक समुदायों के बीच संघर्ष अक्सर होते हैं, इसलिए हिंसा की घटनाओं को कमने की दिशा में क्षेत्रीय एकीकरण एक शांतिपूर्ण प्रगति है। दोनों पक्षों के पारस्परिक समझौते के लिए विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से ठाने की संभावना के बारे में निर्णय लेने

वाला का अनाभृता के कारण अक्सर दग्ध या हिंसा होती है। इस प्रकार यह संभव है कि सामुदायिक विवादों के निपटारे के लिए वैकल्पिक, शांतिपूर्ण तकनीकों को विकसित और संस्थागत बनाकर और राज्यों को उनका उपयोग करने के लिए राजी करके दंगों की रोकथाम में योगदान दे सकते हैं।

इसे राजनीतिक, क्षेत्रीय या साधीय सुरक्षा

इस राजनीतिन, देशन का राष्ट्रीय युत्कृष्ट व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक इकाई यह स्वीकार करती है कि किसी एक की सुरक्षा भी सभी की सामूहिक चिंता है। अतः वे खतरों और शाति के उल्लंघन के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार, देश में में चल रहे जातीय संघर्ष को देखते हुए यह उद्घरण समकालीन समय के लिए प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची जीत ज्ञान और दूरदर्शिता के साथ संघर्षों से निपटने और हिंसा से बचने के लिए शांतिपूर्ण समाधान खोजने से हासिल की जाती है। इसके अलावा, इसे न केवल हिंसा के लिए बल्कि रोजमरा के संघर्षों और चुनौतियों पर भी लागू किया जा सकता है। साथ ही, यह उद्घरण सफलता प्राप्त करने के लिए तैयारी, ज्ञान और दूरदर्शिता के महत्व पर भी जोर देता है। हिंसा के शिकार लोगों को समझाना जरुरी है। बदला लेने की मानसिकता नुकसान करवाती है, ताकि वो फिर उसी हिंसक दुष्कर में न फंस जाएं। कोई शराबी है या ड्रग का आदी है, तो उसकी इलाज करने में मदद की जाती है। फिर उसे रोजगार दिलाने की कोशिश होती है। तभी कोई भी शख्स एकदम से बदला हुआ नज़र आ सकता है। लोगों के बर्ताव में बदलाव लाकर हम कई चुनौतियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। जैसे साफ-सफाई की आदत से डायरिया जैसी बीमारी को रोका जा सकता है। ये कदम तब और असरदार हो जाते हैं, जब एक पीड़ित, दूसरे की मदद करता है। वो अपने खुद के तजुर्बे साझा कर के लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। जैसे कोई टीबी-हैजा के मरीज रहे लोग इसके शिकार लोगों के बीच काम करें।

शिक्षा बोच में छाड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति चिन्ताजनक

रादा

20



मृतकाल को सार्थक बनाने में शिक्षा ही वार्धिक महत्वपूर्ण हो जाती है। कहा जा सकता है कि शिक्षा ही केसा हथियार भी है जो सभसे इंसान न केवल पढ़ाई का स्तर व माहौल उचित नहीं है? सरकार और देश के शिक्षाविदों को इस तथ्य को लेकर भी चिंता करनी ही होगी कि बीते पांच साल में इन उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले 92 विद्यार्थियों ने पढ़ाई के बीच में ही आत्महत्या क्यों कर ली? ऐसे ही अईआईटी बम्बई के फर्स्ट ईयर के छात्र दर्शन

परकारी कॉलेजे नहीं बल्कि आईआईटी, इनआईटी और आईआईएसईआर, आईआईएम व केन्द्रीय विश्वविद्यालय और उनके जैसे स्तर के हैं। ऐसे संस्थानों में क्या पढ़ाई का स्तर व माहौल उचित नहीं है? परकार और देश के शिक्षाविदों को इस तथ्य को लेकर भी चिंता करनी ही होगी कि बीते बांध साल में इन उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रविलाल लेने वाले 92 विद्यार्थियों ने पढ़ाई के बीच में ही आत्महत्या कर्यों कर ली? ऐसे ही आईआईटी बुम्बई के फर्ट ईयर के छात्र दर्शन नोलंकी ने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली, उसके बाद वहां के छात्रों से अधिकारिक तौर पर कहा गया है कि छात्र एक दूसरे से जी (एडवांस) रैंक या गेट स्कोर के बारे में पूछताछ न करें। न ही ऐसा कोई सवाल करें जिससे छात्र की जाति और उससे जुड़े पहलू उजागर होते हों। इस तरह की गाइडलाइन की जरूरत केवल आईआईटी बुम्बई को ही नहीं, बल्कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को है। तीकिन सवाल तो यह भी है कि क्या ऐसे सांकेतिक कदमों से आत्महत्या की बढ़ती परंछा जैसी गंभीर समस्याओं को हल किया जा सकता है। किसी भी देश की शिक्षा

बोरिंग न लगे हैं।
आते-आते काले
बोरिंग लगने लगते हैं।
कलेज देरी से बढ़ाइ
कर देते हैं और
पढ़ाई से लगाव
छात्र स्कूल-काले
वजह से छात्र
करना, पैरेंट्स का
लेकिन यह शिखाए
भी इशारा भी दे
बच्चों को।
शिक्षा ग्रहण करने
है ही, शिक्षा विषय
में भी प्रमुख
मौजूदा समय
प्रबंधन इसे एक
लगे हैं, सरकारी
भाग रही है,
कानून लागू है,
बहुत सारी चीज़ें
बच्चों का नाम
पास करने वाले
तेज़ी से बढ़े हैं,
गणतना और ज

समान कानून पर थम गई च्या अनीत दिलेती प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी

866

राष्ट्राय विवाद आयाग का समान नागरिक सहित यानी यूसीसी पर 80 लाख से एक करोड़ के बीच सुझाव मिले हैं। आयोग ने 14 जून को लोगों से अपील की थी कि वे बताएं कि देश में समान नागरिक सहित लागू होनी चाहिए या नहीं। अगर होनी चाहिए तो क्यों और नहीं होनी चाहिए तो उसके पछे क्या तर्क है। पहले एक महीने का समय दिया गया था लेकिन बाद में इसे दो हफ्ते और बढ़ा दिया गया। इस बीच 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य काइ बयान नहीं दिया ह। काइ और मंत्री या भाजपा का नेता भी इस बारे में नहीं बोल रहा है और इस पर होने वाले सेमिनार, सम्मेलन आदि भी अचानक बंद हो गए हैं। सबाल है कि ऐसा क्यों हुआ है? क्या इस कानून को लागू करने के रास्ते में आने वाली बाधाओं या विरोधाभासों की वजह इसको स्थगित कर दिया गया है या सरकार की कोई मंशा थी, जो इतनी चर्चा से ही पूरी हो गई है और उसके बाद उसे स्थगित कर दिया गया है?

प्रदेश में भाजपा के चुनाव अभियान का आगाज करते हुए समान नागरिक संहिता पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर दो कानून से घर नहीं चल पाएगा। भारत के सविधान में भी नागरिक के समान अधिकार की बात की गई है।' प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद पूरे देश में समान कानून पर चर्चा शुरू हो गई। चारों तरफ इस पर सम्मेलन और सेमिनार होते लगे। संहिता के बारे में यह आम धारणा है कि इसका सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय करेगा। आजादी के बाद से भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और 1980 के बाद से भाजपा ने यह धारणा बनाई है कि कांग्रेस की सरकारों ने अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण करने के लिए इसे लागू नहीं किया, जबकि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में इसको शामिल किया गया है। लेकिन हकीकत इस पचारित धारणा से अलग है।



रहा है। संसद में दिये गये एक जबाब के अन्तर्मार्ग देश के नामी उच्च शिक्षण संस्थानों

यथवस्थ की कामयाबी इसमें है कि शुरुआती तरीके से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा हासिल करने के मामलों में एक निरतरा हो। अगर किसी वजह से आगे की पढाई करने में किसी विद्यार्थी के सामने अड़चनें आ रही हो तो उसे पूर करने के उपाय किये जाएं। लेकिन बीते कई दशकों से यह सवाल लगातार बना हुआ है कि एक बड़ी तादाद में विद्यार्थी स्कूल-कॉलेजों में बीच में ही पढाई छोड़ देते हैं और उनकी आगे की पढाई को पूरा कराने के लिए सरकार की ओर से ठोस उपाय नहीं किए जाते। इस मसले पर सरकार से लेकर शिक्षा विभाग काम करने वाले संगठनों की अध्ययन पटों में अनेक बार इस चिता को रेखांकित किया गया है, लेकिन अब तक इसका कोई सार्थक हल सामने नहीं आ सका है।

तमाम स्पष्टकारी प्रयासों प्रवृत्त योजनाओं के

तमाम सरकारों प्रयासों एवं योजनाओं के द्वारा शिक्षा महंगी होती जा रही है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, स्तर के स्कूलों एवं कालेजों में प्रवेश असंभव होने से निजी स्कूलों एवं कालेजों में बच्चों को पढ़ाना विवशता बनती जा रही है। कोई परिवार हिम्मत करके निजी कूट्ठों एवं कालेजों में प्रवेश दिलाते भी है तो आर्थिक मजबूरी के कारण उन्हें बीच में बच्चों को स्कूल से निकाल लेने को विवश होता पड़ता है। सरकार की बड़ी-बड़ी योजनाओं के बीच छात्रों के स्कूल-कालेज ड्रेडने की स्थितियों को गंभीरता से लेना चाहिए। शिक्षा को पेंचिदा बनाने की बजाय सहज, निष्टंक, कम खर्चीली एवं रोचक बनाना होगा। शिक्षा को रोचक बनाना भी नातंत्र स्तर का ही सुचक है। इतने लंबे वक्त क्यों नहीं इस पहुंचना एक ऐसा चिन्तन-मंथन है। एक और स्कूल तथा मानक बहुत सहजता से ग्रन्थित होने वाली निरंतरता नहीं स्वरूप से बदल सकती। सामाजिक और दृष्टि बिंदुओं को एक जरूरत होगी।

मैं पिछले पांच साल के दौरान 34 हजार से ज्यादा छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ गए। दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से सन् 2022 की बोर्ड परीक्षाओं के विश्लेषण में बताया गया है कि दसवीं और बारहवीं के स्तर पर देश में लाखों बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं।

विश्लेषण के मुताबिक, पिछले साल पैंतीस लाख विद्यार्थी दसवीं के बाद ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने नहीं गए। इनमें से साढ़े सत्ताइस लाख सफल नहीं हुए और साढ़े सत्त लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। इसी तरह, पिछले साल बारहवीं के बाद 2.34 लाख विद्यार्थियों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। इनमें से सतहतर फ्रेसद ग्यारह राज्यों से थे। यानी

कराब अड्डाक्वन लाख त्रिलयोदशा दसवा आर
बारहवीं में पढाई छोड़ देते हैं तो यह किसी भी
सरकार के लिए बेहद चिंता की बात होनी
चाहिए और यह समग्र शिक्षा व्यवस्था से
लेकर सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के जमीनी
स्तर पर अमल पर सवालिया निशान है।

बात उच्च शिक्षा की करें तो वैश्विक
मापदण्डों पर हमारी शिक्षण संस्थाएं काफी पीछे
नजर आती हैं। यह तो तब है जब आजादी
के 76 सालों में सरकारों ने शिक्षा के प्रसार
की दिशा में काफी प्रयास किये, बहुआयामी
योजनाओं को आकार दिया एवं बजट में भी
भारी भरकम प्रावधान किये हैं। 34 हजार से
ज्यादा बीच में ही पढाई छोड़ देने वाले छात्रों
में भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के

प्रयासों के बीच इस हकीकत पोड़ा या जा सकता कि दुनिया के शिक्षण संस्थानों में भारत से अधिक हैं। आज भी सक्षम परिवारों के लिए पहली पसंद विदेश न बने हुए हैं। संसाधनों की विदेशी शिक्षकों का अभाव इसकी वजह है। लेकिन यह भी सही है कि रखैये के चलते हमारे वाले शिक्षण संस्थानों में भी ल नहीं बन पाता। सरकारी नीतिगत स्तर पर शिक्षा को एक मिलती दिखती है, बावजूद विदेशी में पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति नाकामी या पिर उदासीनता। यह समझना मुश्किल है कि से यह चिंता कायम है पिर मसले पर किसी हल तक नहीं सवाल है जिस पर व्यापक रुरी है। यह जगजाहिर है कि -कालेज में शिक्षा पद्धति में त सारे विद्यार्थियों के लिए नहीं होते, वहीं पढ़ाई में हने के पीछे पठन-पाठन के लिए गरीबी, परिवारिक, अन्य कई कारकों से जुड़ा सके समाधान के लिए सभी सत्र में रखकर ही देखने की ऐसी खबर आई थी कि उत्तराखण्ड सरकार की ओर से तैयार कराए जा रहे बिल के मसौदे को ही भारत सरकार भी अपना सकती है। उत्तराखण्ड सरकार के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी कर रही है। पिछले महीने इस कमेटी के सदस्यों ने विधि आयोग से भी मुलाकात की थी। तब कहा गया था कि 15 जुलाई तक जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। हैरानी की बात है कि अब जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमेटी की ओर से बनाए जा रहे मसौदे की भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं सौंपी। सो, रेफरेंस के लिए भी किसी के पास कोई मसौदा नहीं है। विधि आयोग को जो एक करोड़ सुझाव मिले हैं उनकी छंटनी और विषय के हिसाब से व्योरेवार उनको व्यवस्थित करना लंबा और समय खाने वाला काम है। इसी तरह 27 जन के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत होगी तो फिर आदिवासियों को इससे बाहर रखने की बात कहां से आई? जाहिर है आदिवासी समुदाय को भी इससे दिक्कत है।

इसके बाद सिख समुदाय ने ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करने का ऐलान किया। सिखों की सबसे बड़ी और पवित्र संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा कि समान नागरिक संहिता सिख संस्कृति, उसकी परंपरा और उसके धार्मिक रीति-रिवाज को प्रभावित करेगी। सिखों के बाद ईसाई समुदाय ने इसका विरोध किया और विरोध की सबसे तीखी आवाज पूर्वोत्तर से आई। वहां मेघालय, नगालैंड, मिजोरम आदि राज्यों में भाजपा की सहयोगी पार्टियों ने कहा कि उनको समान नागरिक संहिता कबूल नहीं है। बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी विधि आयोग को भेजी गई अपनी सलाह में इस तरह के किसी प्रयास का विरोध किया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कट्टरपंथी हिंदू बौद्धिकों ने भी इसका विरोध किया।

एक नजर

कलेज में मनाई गई रविशंकर शुक्ल की जयंती



महासमृद्ध। शासकीय महाप्रभु लभावार्य सताकोटर महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा पांडित रविशंकर शुक्ल जयंती मनाई गई। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. रीता पांडे, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग डॉक्टर मालती तिवारी, डॉक्टर दुवारी भारतीय विभाग अध्यक्ष हिंदौ, डॉ. नीलम अग्रवाल विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र, अजय कुमार राजा नोडल स्थामी आमा नंद इंगलिश मिडिम महाविद्यालय, सीमा रामी प्रधान, केशर चंद्र बनपाल, अशुतोष पूरी गोमामी, मनीषा देवरा, नम्रता तवारी, जिया कुमार मिर्ज़, एमपे राजनीति विज्ञान प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं मौजूद रहे संप्रवेष्य पांडित रविशंकर शुक्ला के छायाचिन्त पर पूजन का कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ किया गया। तत्पश्त तुम्हें अतिथि को आसदी से संबोधित करते हुए डॉक्टर रीता पांडे ने शुक्ल के राजनीतिक जीवन पर कार्राया डालते हुए कहा कि किस प्रकार स्थानीय आदोलन में बढ़कर हिस्सा लिया। और राष्ट्रीय आदोलन को छींसार्ड में जीवन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर मालती तिवारी ने पांडित रविशंकर शुक्ल के सक्षिप्त जीवन परिचय बताते हुए बताया कि 2 अगस्त 1877 को मध्यप्रदेश के सागर में शुक्ल का जन्म हुआ। वे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, स्वतंत्रता संशाम सेनानी एवं 1 नवम्बर 1956 में अपने अस्तित्व में आए।

खेलगढ़िया मद में भ्रष्टाचार के आरोपी को बना दिया खेल अधिकारी, कलेक्टर से जांच रिपोर्ट मांगी

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

राजिम, 3 अगस्त। गरियाबंद जिले में समग्र शिक्षा विभाग के तत्कालीन जिला परियोजना समन्वय विभाग चंद्रकर पर खेलगढ़िया मद की रोशन से स्कूलों में टीकी खरीदने और जम कर अनिवार्यता बत कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थे जिसके जांच करेकर ने जांच समिति बनाई थी जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी शामिल रहे अपर कलेक्टर गरियाबंद के सदस्यों ने जांच में तत्कालीन डॉ. एम. सी. श्याम चंद्रकर को दबोचा मानते हुए अपर धांधली की गई थी। जब इस मामले की सूचना के अधिकार अधिनियम से जांच में दबोचा पाए जान पर कारबाही हेतु संचालक लोक शिक्षण जिले के बच्चों के लिए खेलगढ़िया मद खरीदी जानी थी। वह टीकी खरीद गया था। एवं विभाग के मैनपुर ब्लॉक सहित गरियाबंद और छात्र ब्लॉक में जमकर धांधली की गई थी। जब इस मामले की सूचना के अधिकार अधिनियम से जांच में दबोचा पाए जान पर कारबाही हेतु संचालक लोक शिक्षण जिले के भेजी कारबाही लंबित रही। ब्लॉक कलेक्टर के विरुद्ध प्रधान मलिक ने श्याम चंद्रकर के विरुद्ध कारबाही हेतु स्कूल के बच्चों के पत्र लिखा फिर भी आज पर्यान्त तक दबोचा पर कारबाही ना कर उसे जिला में खेल समिक्षकों ने दुकाकर से मिलकर फौजी बिल लाए व राशि हड्डप कर लिए थे। खास बात यह है कि आज भी इस मामले का लेकर लोग बेसबी से कारबाही होने हो और लोग बेसबी से कारबाही करते हैं।

हो रही है। और गरियाबंद जिले के प्रशासनिक व्याप्ति पर सबल खड़े हो रहे हैं। जिसमें श्याम लोगों को प्रशासनिक संरक्षण देकर सकार की ओर प्रशासन खराब कर रहा वहीं मामले पर संचालक लोक शिक्षण ने पुक़ कारबाही के करने कलेक्टर गरियाबंद को मूल जांच प्रतिवेदन मांगी है ताकि कारबाही कर सके। बता दे की ताकालिक डॉ. एम. सी. श्याम चंद्रकर ने खेलगढ़िया मद की रोशन से स्कूलों में टीकी खरीदने और जम कर अनिवार्यता बत कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थे जिसके जांच करेकर ने जांच समिति बनाई थी जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी शामिल रहे अपर कलेक्टर गरियाबंद सहित गरियाबंद और छात्र ब्लॉक में जमकर धांधली की गई थी। जब इस मामले की सूचना के अधिकार अधिनियम से जांच में दबोचा पाए जान पर कारबाही हेतु संचालक लोक शिक्षण जिले के भेजी कारबाही लंबित रही। ब्लॉक कलेक्टर के विरुद्ध प्रधान मलिक ने श्याम चंद्रकर के विरुद्ध कारबाही हेतु स्कूल के बच्चों के पत्र लिखा फिर भी आज पर्यान्त तक दबोचा पर कारबाही ना कर उसे जिला में खेल समिक्षकों ने दुकाकर से मिलकर फौजी बिल लाए व राशि हड्डप कर लिए थे। खास बात यह है कि आज भी इस मामले का लेकर लोग बेसबी से कारबाही होने हो और लोग बेसबी से कारबाही करते हैं।

डाकघरों में हो रही झांडों की बिक्री



रायगढ़, 3 अगस्त। विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मनाया जा रहा है। भारतीय डाक विभाग देश भर में अपनी पहुंच और जनसत्तिक का उपयोग करते हुए हर घर तिरंगा अधियान के महात्व के बारे में लोगों को जागरूक करने देश के 1.6 लाख डाक घरों से झंडा का विरुद्ध कारबाही हेतु जिले के मैनपुर ब्लॉक सहित गरियाबंद और छात्र ब्लॉक में जमकर धांधली की गई थी। जब इस मामले की सूचना के अधिकार अधिनियम से जांच में दबोचा पाए जान पर कारबाही हेतु संचालक लोक शिक्षण जिले के भेजी कारबाही लंबित रही। ब्लॉक कलेक्टर के विरुद्ध प्रधान मलिक ने श्याम चंद्रकर के विरुद्ध कारबाही हेतु स्कूल के बच्चों के पत्र लिखा फिर भी आज पर्यान्त तक दबोचा पर कारबाही ना कर उसे जिला में खेल समिक्षकों ने दुकाकर से मिलकर फौजी बिल लाए व राशि हड्डप कर लिए थे। खास बात यह है कि आज भी इस मामले का लेकर लोग बेसबी से कारबाही होने हो और लोग बेसबी से कारबाही करते हैं।

छुरा विकासखंड से आज तक एक भी राजनीतिक पार्टी ने विस्त प्रत्याशी नहीं बनाया

राजिम (छुरा) इस बार फिर विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी को लेकर जगह जगह दीवारों में राजनीतिक दलों के लोग अपना प्रचार चालू कर रहे हैं जिसमें काई नेता केंद्र की ओर उपलब्ध बता रहे हैं तथा काई राज्य की विभिन्न योजनाओं का गुणावन कर रहे हैं। तथा विधान सभा राजिम के सभी गांव की दीवारों में लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में असानी से देखा जा सकता है फैसलों की बात यह एक इनमें से कुछ ऐसे भी गांव है जिसमें जांचे हुए प्रत्याशी भले ही आज तक ना पहुंचे हो पर उसके कार्यकर्ता दीवारों में प्रचार के माध्यम से जरूर पहुंच गए हैं। राजिम विधानसभा बने लगभग 71 साल हो गए हैं और इन 71 सालों में विकासखंड छुरा से आज तक एक भी प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं आए गए एक बार किस विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में नहीं लगता कि लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में असानी से देखा जा सकता है फैसलों की बात यह एक इनमें से कुछ ऐसे भी गांव है जिसमें जांचे हुए प्रत्याशी भले ही आज तक ना पहुंचे हो पर उसके कार्यकर्ता दीवारों में प्रचार के माध्यम से जरूर पहुंच गए हैं। राजिम विधानसभा बने लगभग 51 साल हो गए हैं और इन 51 सालों में विकासखंड छुरा से आज तक एक भी प्रत्याशी किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं आए गए एक बार किस विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में नहीं लगता कि लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में असानी से देखा जा सकता है फैसलों की बात यह एक इनमें से कुछ ऐसे भी गांव है जिसमें जांचे हुए प्रत्याशी भले ही आज तक ना पहुंचे हो पर उसके कार्यकर्ता दीवारों में प्रचार के माध्यम से जरूर पहुंच गए हैं। राजिम विधानसभा चुनाव 1952 में जीते और 1962 तक विधायक रहे हैं। और अपने अधिकारियों के द्वारा देखा जाता है कि लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में असानी से देखा जा सकता है फैसलों की बात यह एक इनमें से कुछ ऐसे भी गांव है जिसमें जांचे हुए प्रत्याशी भले ही आज तक ना पहुंचे हो पर उसके कार्यकर्ता दीवारों में प्रचार के माध्यम से जरूर पहुंच गए हैं। राजिम विधानसभा चुनाव 1952 में जीते और 1962 तक विधायक रहे हैं। और अपने अधिकारियों के द्वारा देखा जाता है कि लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में असानी से देखा जा सकता है फैसलों की बात यह एक इनमें से कुछ ऐसे भी गांव है जिसमें जांचे हुए प्रत्याशी भले ही आज तक ना पहुंचे हो पर उसके कार्यकर्ता दीवारों में प्रचार के माध्यम से जरूर पहुंच गए हैं। राजिम विधानसभा चुनाव 1990 से लेकर 1998 तक एक भी प्रत्याशी का दबदबा रहा और उपचुनाव में वर्तमान विधायक राजिम अधिकारी शुक्रल को पहला मोका मिला और उन्होंने जीत हासिल की और राजिम विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया तो वही 2003 में भाजपा प्रत्याशी चंद्रुलाल साहू ने अमितेश को हराकर इस सीट पर कब्जा किया। यहीं वह एक भी प्रत्याशी का दबदबा रहा और उपचुनाव में वर्तमान विधायक राजिम अधिकारी शुक्रल को पहला मोका मिला और उन्होंने जीत हासिल की और राजिम विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया तो वही 2003 में भाजपा प्रत्याशी चंद्रुलाल साहू ने अमितेश को हराकर इस सीट पर कब्जा किया। यहीं वह एक भी प्रत्याशी का दबदबा रहा और उपचुनाव में वर्तमान विधायक राजिम अधिकारी शुक्रल को पहला मोका मिला और उन्होंने जीत हासिल की और राजिम विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया तो वही 2003 में भाजपा प्रत्याशी चंद्रुलाल साहू ने अमितेश को हराकर इस सीट पर कब्जा किया। यहीं वह एक भी प्रत्याशी का दबदबा रहा और उपचुनाव में वर्तमान विधायक राजिम अधिकारी शुक्रल को पहला मोका मिला और उन्होंने जीत हासिल की और राजिम विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। यहीं वह एक भी प्रत्याशी का दबदबा रहा और उपचुनाव में वर्तमान विधायक राजिम अधिकारी शुक्रल को पहला मोका मिला और उन्होंने जीत हासिल की और राजिम विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। यहीं वह एक भी प्रत्याशी का दबदबा रहा और उपचुनाव में वर्तमान विधायक राजिम अधिकारी शुक्रल को पहला मोका मिला और उन्होंने जीत हासिल की और राजिम विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। यहीं वह एक भी प्रत्याशी का

